

अजय

3 रूपये मात्र



लखनऊ, शुक्रवार 6 नवम्बर, 2026 | नगर संस्करण पृष्ठ-12 | गौरवशाली परंपरा का २०० वर्ष | Online Edition : www.ajhindidaily.com

वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, (मध्य प्रदेश संस्करण), कानपुर, (झांसी संस्करण), लखनऊ , आगरा, बरेली, पटना, रांची, (धनबाद संस्करण) तथा जमशेदपुर से प्रकाशित

यूपी : राज्य कर्मियों को 30 दिन का बोनस



लखनऊ (आससे.)। प्रदेश सरकार ने राज्य के लाखों कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए वर्ष 2025-2026 के लिए 30 दिन के तदर्थ बोनस के भुगतान को मंजूरी दे दी है। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद वित्त विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने बृहस्पतिवार को शासनादेश जारी कर दिया। इस फैसले से राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण

अधिकतम ६९०८ रुपये मिलेंगे, ७५ प्रतिशत रकम जीपीएफ में जमा होगी

एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा। शासनादेश के मुताबिक, यह बोनस उन सभी पूर्णकालिक अराजपत्रित कर्मचारियों को दिया जाएगा।

पंजाब में पिस्टल, हैंड ग्रेनेड-३४ किलो हेरोइन बरामद, १६ गिरफ्तार

अमृतसर (एजेंसी)। अमृतसर देहात पुलिस ने अवैध हथियारों, विस्फोटक सामग्री और नशा तस्करी से जुड़े अलग-अलग नेटवर्क के खिलाफ कारवाई करते हुए 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से पांच अवैध पिस्तौल, दो अत्याधुनिक उजी गन, दो हैंड ग्रेनेड, 34 किलो हेरोइन और 26 कारतूस बरामद किये हैं। इसके साथ ही पुलिस ने फायरिंग की तीन वारदातों को भी सुलझाने का दावा किया है। पुलिस के अनुसार, शुरुआती जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपी विदेश में बैठे हैंडलरों के संपर्क में थे।

अब छह राज्यों-केंद्र शासित प्रदेशोंमें होगा एसएसआर

नयी दिल्ली (आससे)। भारत निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) की घोषणा की। इस प्रक्रिया का उद्देश्य पात्र मतदाताओं, खासकर युवाओं और पहली बार वोट देने वाले लोगों के नाम मतदाता सूची में शामिल करना है। आयोग के मुताबिक, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, मिजोरम, ओडिशा और सिक्किम में यह अभियान चलाया जायेगा।

दिल्ली : चावड़ी बाजारमें अचानक ढही तीन मंजिला इमारत, दो की मौत

नयी दिल्ली (आससे)। दिल्ली के चांदनी चौक स्थित चावड़ी बाजार के गली सत्तारा, शीश महल इलाके में गुरुवार को एक निर्माणाधीन तीन मंजिला इमारत का हिस्सा ढहने से दो लोगों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हो गए। हादसा चावड़ी बाजार मेट्रो स्टेशन के पास हुआ। मलबे में कुछ और लोगों के दबे होने की आशंका के चलते एनडीआरएफ, दिल्ली पुलिस, दमकल और डीडीएमए की



टीमें राहत एवं बचाव अभियान में जुटी रहीं।मृतकों की पहचान 40 वर्षीय किशोरी और 45 वर्षीय संजीत के रूप में हुई है। दोनों मंडावली की रेलवे कॉलोनी के निवासी थे। घायलों सहदेव चौधरी (25) और फिरोज (37) की हालत स्थिर बताई गई है।

शिकायतों का इंतजार कर जांच नहीं रोक सकते-सुप्रीम कोर्ट



नयी दिल्ली (आससे)। नीट प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस ज्यादती की जांच में देरी पर सुप्रीम

नीट प्रदर्शनमें पुलिस ज्यादतीपर की सख्त टिप्पणी

कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने हाई-पावर्ड कमेटी को निर्देश दिया कि शिकायतें कम मिलने या नई शिकायतों का इंतजार करने के नाम पर जांच अनिश्चितकाल तक लंबित नहीं रखी जा सकती। कमेटी अब तक उपलब्ध दस्तावेजों और साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाए और फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पेश करने की प्रक्रिया शुरू करे। सुनवाई के दौरान कमेटी ने अदालत को बताया कि उसे अब तक अपेक्षाकृत कम शिकायतें मिली हैं।

यूपी अब देश की तीन शीर्ष अर्थव्यवस्थाओंमें शामिल-योगी

प्रदेशमें कानून व्यवस्था-शासन व्यवस्थामें भी हुआ व्यापक सुधार



लखनऊ (आससे)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को कहा कि राज्य ने पिछले नौ वर्षों में उल्लेखनीय बदलाव करते हुए आर्थिक रूप से देश के सबसे पिछड़े पांच राज्यों की श्रेणी से निकलकर शीर्ष तीन राज्यों में जगह बनाई है। उन्होंने दावा किया कि इस दौरान कानून-व्यवस्था और शासन व्यवस्था में भी व्यापक सुधार हुआ है। मुख्यमंत्री यहां 28 नवनियुक्त अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित करने के लिए आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक समय उत्तर प्रदेश अराजकता, दंगों और कर्फ्यू के दौर से गुजर रहा था तथा अपराधियों को कानून का कोई भय नहीं था। योगी ने कहा एक समय था जब अपराधी बेखौफ घूमते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा।

यूपी : राहुल के खिलाफ एफआईआरकी मांग खारिज, इलाहाबाद हाईकोर्टका बड़ा फैसला



प्रयागराज (आससे.)। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सिख समुदाय

सिख समुदायपर आपत्ति-जनक टिप्पणीका मामला

पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है।

भाजपाने बहुमतके लिए गोकुल डेयरी चुनावके लिए नियम बदले-राहुल

नयी दिल्ली (आससे.)। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र की गोकुल डेयरी के चुनाव को लेकर बीजेपी पर चुनाव के बाद नियम बदलकर बहुमत छीनने का आरोप लगाया है। उन्होंने इसे दूध उत्पादकों के वोटों की चोरी बताया। राहुल गांधी ने गुरुवार को एक्स पर लिखा- गोकुल में दूध डेयरी चलाने वालों ने भाजपा को हरा दिया।

जौनपुर को मिली 3650 करोड़ की सड़क परियोजनाओं की सौगात



जौनपुर (ह.स.)। मुंगराबादशाहपुर स्थित सार्वजनिक इंटर कॉलेज परिसर में गुरुवार को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की उपस्थिति में 3650 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली आठ राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया। इस दौरान 3210 करोड़ रुपये की लागत से पूरी हुई रायबरेली-प्रयागराज फोरलेन, जगतपुर-बाबूगंज-ऊंचाहार-आलापुर बाईपास और मछलीशहर-जंघई-भदोही मार्ग सहित तीन परियोजनाओं को जनता को समर्पित किया गया। वहीं करीब 400 करोड़ रुपये की लागत से पांच नई परियोजनाओं का कार्य शुरू कराया गया।

टीएमसी विधायकके ऑफिससे १.०२ करोड़ जब्त

कोलकाता (एजेंसी)। बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के डायमंड हार्बर में तृणमूल कांग्रेस कार्यालय से पुलिस ने 1.02 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी बरामद की है। ये ऑफिस बागी टीएमसी विधायक शमीम अहमद का बताया जा रहा है। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ने राज्य का सारा राजस्व हड़प लिया था। यह तो बड़े भ्रष्टाचार का छोटा हिस्सा है। टीएमसी ने कहा है कि पुलिस ने निगरानी में रखे गए कार्यालय में जानबूझकर झूठे सबूत प्लांट किए हैं। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि यह पैसा उनके(ममता-अभिषेक) लिए यह कुछ भी नहीं है। यह उनकी रोज की कमाई थी।

मथुरा : हादसेमें पिता-पुत्र समेत तीन की मौत

मथुरा (आससे)। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में गुरुवार सुबह अनियंत्रित होकर खेत में घुसी तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से पिता-पुत्र समेत एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो गई जबकि कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि हादसा राया थाना क्षेत्र के गजू गांव के पास भरतपुर-पीलीभीत राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ। पुलिस उपाधीक्षक संजीव कुमार राय ने बताया कि सुबह करीब आठ बजे गजू गांव निवासी जवाहर सिंह (70), उनके बेटे हरवीर सिंह (45) और नाती अंकित (24) खेत में अपने पूर्वजों की समाधि का जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण करा रहे थे।

नागौर में पटाखों के गोदाम में भीषण धमाका, दो की मौत

नागौर (एजेंसी)। राजस्थान के नागौर जिले के बड़ली इलाके में गुरुवार सुबह पटाखों के गोदाम में हुए भीषण विस्फोट में दो युवकों की मौत हो गयी। दोनों मृतक आपस में चचेरे भाई थे और नागौर शहर के बाजरवाड़ा इलाके के रहने वाले थे। धमाका इतना जोरदार था कि गोदाम की छत उड़ गयी और आसपास के मकानों की दीवारों में दरारें आ गईं। घटनास्थल से करीब 100 फीट दूर खड़ी बस के शीशे तक टूट गये। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट से निकली चिंगारी के कारण विस्फोट होने की आशंका जतायी जा रही है। हालांकि, पुलिस का कहना है कि धमाके की वास्तविक वजह जांच के बाद ही स्पष्ट होगी। नागौर के सीओ जतिन जैन के अनुसार, पटाखों के गोदाम की फैक्ट्री के खुले आंगन में बिजली का पोल भी लगा हुआ है। शुरुआती जांच में आशंका जतायी जा रही है कि बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट होने से निकली चिंगारी के कारण विस्फोट हुआ होगा।

नाबालिग की सहमति का कोई महत्व नहीं दुष्कर्म के आरोपी की जमानत खारिज

हाथरस (एजेंसी)। हाथरस विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कोर्ट प्रथम ने नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने, दुष्कर्म करने व गर्भवती करने के मामले में आरोपी हिमांशु यादव की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने अपने फैसल में कहा कि नाबालिग की सहमति का कानून की नजर में कोई विधिक महत्व नहीं है। मामला थाना कोतवाली हाथरस जंक्शन क्षेत्र का है। किशोरी के पिता ने दो सितम्बर को थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी थी। आरोप था कि एक सितंबर को उनकी 17 वर्षीय बेटी को हिमांशु यादव बहला-फुसलाकर ले गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना के बाद आरोपी के खिलाफ धारा अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो अधिनियम के तहत न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि पीड़िता स्वेच्छा से गयी थी और उसने पुलिस व मजिस्ट्रेट के समक्ष बयानों में आरोपी पर अपहरण या दुष्कर्म का कोई आरोप नहीं लगाया है। दोनों एक-दूसरे से प्रेम करते हैं और मंदिर में शादी कर चुके हैं। विशेष लोक अभियोजक ने जमानत का कड़ा विरोध करते हुए तर्क दिया कि पीड़िता नाबालिग है और चिकित्सीय जांच के अनुसार वह लगभग 19-20 सप्ताह की गर्भवती है। अदालत ने पत्रावली व साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अपने आदेश में स्पष्ट किया कि पीड़िता की आयु 17 वर्ष है यानी वह नाबालिग है, इसलिए उसकी सहमति का कानून की नजर में कोई विधिक महत्व नहीं रह जाता। अपराध की जघन्यता और गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने अभियुक्त हिमांशु यादव का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।

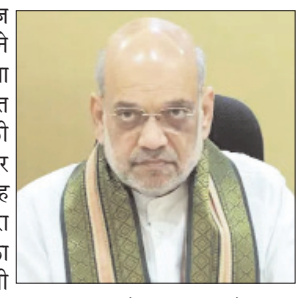
यूजीसी के नए समानता नियमों पर फिर होगा विचार

सुप्रीम कोर्ट में केन्द्र का जवाब हो रही समिति बनाने की तैयारी

नयी दिल्ली। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने वाले 2026 के नियमों को लेकर केंद्र सरकार एक बार फिर विचार कर रही है। सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह इन नियमों की समीक्षा के लिए एक समिति गठित करने पर विचार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे की जांच कर रही है, ताकि विद्यार्थियों की चिंताओं का समाधान किया जा सके। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि किसी भी वर्ग को असंतोष या आशंका महसूस न हो। तुषार मेहता ने अदालत में कहाकि सरकार एक समिति नियुक्त करने पर विचार कर रही है। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार ने तय किया है कि हर विद्यार्थी का ध्यान रखा जाना चाहिए। नई पीढ़ी के हितों को ध्यान में रखते हुए इस विषय पर विचार किया जा रहा है। सीजेआई ने कहा कि इस प्रक्रिया में सभी छात्रों के हितों की रक्षा होनी चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि युवा पीढ़ी की चिंताओं और उनके भले को सबसे अहम माना जाना चाहिए। केंद्र सरकार की ओर से समिति गठित करने पर विचार किए जाने की जानकारी मिलने के बाद अदालत ने संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई चार सप्ताह के लिए टाल दी। यह मामला अबेदा सलीम तडवी बनाम भारत संघ और इससे जुड़ी अन्य याचिकाओं से संबंधित है। इससे पहले, कोर्ट ने 2026 के नियमों पर रोक लगा दी थी, क्योंकि उसे लगा था कि इनके प्रावधान अस्पष्ट हैं और इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। कोर्ट ने निर्देश दिया था कि जब तक इस पर आगे कोई फैसला नहीं लिया जाता, तब तक यूजीसी के 2012 के समानता नियम लागू रहेंगे।

देश से घुसपैठियों को चुन-चुनकर बाहर निकालेंगे-शाह

हरियाणा (एजेंसी)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हरियाणा के दौरे पर हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने करनाल में एक किमी की लोकतंत्र बचाओ अराजकता हटाओ पदयात्रा की। मंच से संबोधन करते हुए अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस की अराजकता व तुष्टीकरण की राजनीति अब पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है और देशवासी इसके खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज हमारी भाजपा द्वारा आयोजित लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ रैली का आखिरी दिन है। 22 अक्बतूर से 5 नवंबर तक, यह रैली



पूरे देश में पार्टी मुख्यालयों पर आयोजित की गयी। हर जगह, हमने एक जैसा उत्साह और भारी भीड़ देखी है। देश भर की सड़कों पर हमारे नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जनता का जबरदस्त समर्थन देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को तीन करोड़ घुसपैठियों की चिंता है, हम एसआईआर पर विशेष सत्र बुलाने के लिए तैयार हैं। हम घुसपैठियों को चुन चुनकर देश से बाहर निकालेंगे। अमित शाह ने कहा कि लोकतंत्र में संसद चर्चा का सर्वोपरि स्थान है। राहुल गांधी संसद चलने नहीं देते हैं, मुद्दों पर चर्चा नहीं करते हैं। संसद में शोर-शराबा, बहिष्कार करने को कांग्रेस ने कल्चर बना दिया है। संसद चलने नहीं देनी है और रोड पर भीड़ इकट्ठा करके अराजकता फैलानी है। कांग्रेस ने रैली के लिए एक नवंबर का दिन चुना।



पाकिस्तान से 28 लाख से अधिक अफगान नागरिक निर्वासित

लाहौर (एजेंसी)। पाकिस्तान ने 2023 से लेकर अब तक 28 लाख से अधिक अफगान नागरिकों को अफगानिस्तान निर्वासित किया है। इनमें देश के पंजाब प्रांत से निर्वासित किये गये 1.43 लाख अफगान नागरिक शामिल हैं। पंजाब सरकार के गृह विभाग की विदेशी राष्ट्रीय सुरक्षा इकाई ने गुरुवार को यह जानकारी दी। इकाई ने बताया कि अब तक पूरे पाकिस्तान से कुल 28.07 लाख अफगान नागरिकों को उनके देश वापस भेजा जा चुका है, जिनमें से 1,43,474 लोगों को सितंबर 2023 के बाद से पंजाब प्रांत से निर्वासित किया गया है। उसने बताया कि सरकार ने पंजाब प्रांत में अवैध रूप से रह रहे अफगान नागरिकों के खिलाफ अपने अभियान को और तेज कर दिया है। इकाई के मुताबिक, यह अभियान संघीय सरकार की इस नीति के अनुरूप चलाया जा रहा है कि बिना वैध वीजा के किसी भी अफगान नागरिक का देश में रहना गैरकानूनी है। उसने बताया कि इस प्रक्रिया के तहत अवैध रूप से रह रहे अफगान नागरिकों को गिरफ्तार किया जा रहा है और प्रांत भर में बनाये गये निरुद्ध केंद्रों में भेजा जा रहा है। इकाई के अनुसार, फिलहाल पंजाब में 39 निरुद्ध केंद्र संचालित किये जा रहे हैं।

नीति आयोग के सदस्यों के साथ प्रधानमंत्री ने की बैठक

नयी दिल्ली (आससे)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नई दिल्ली में नीति आयोग की नई टीम के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक की है। यह मुलाकात ऐसे समय पर हुई है जब दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है और ग्लोबल

विकसित भारत २०४७ पर मंथन

लेवल पर कई तरह की चुनौतियां सामने आ रही हैं। सरकार के इस शीर्ष थिंक टैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री का मुख्य मकसद यह जानना था कि आयोग के नए सदस्य इस समय किन-किन अहम मुद्दों और नीतियों पर जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। इस हाई-लेवल बैठक के दौरान नीति आयोग के सदस्यों ने प्रधानमंत्री के सामने एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन रखी। इसमें उन सभी खास नीतियों और सेक्टरों का जिक्र किया गया जिन पर आयोग इन दिनों तेजी से काम कर रहा है। अधिकारियों ने साफ किया कि यह पूरा एजेंडा सरकार के साल 2047 तक देश को एक विकसित राष्ट्र यानी विकसित भारत बनाने के विजन के बिल्कुल मुताबिक तैयार किया गया है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को



आने वाले दशकों में और ज्यादा मजबूत बनाया जा सके। इस अहम बैठक में नीति आयोग की पूरी नई लीडरशिप ने खुलकर हिस्सा लिया और अपने-अपने विभागों का अपडेट साझा किया। इस बैठक में मुख्य रूप से निम्नलिखित वरिष्ठ अधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक लाहिरी और सीईओ अनुराग जैन इस बैठक में प्रमुख रूप से शामिल हुए। आयोग के पूर्णकालिक सदस्यों में राजीव गाउबा, आर. बालासुब्रमण्यम और जोरम अनिया ने अपनी बात रखी। इसके अलावा के.वी. राजू, एम. श्रीनिवास, गोबर्धन दास और अभय करंदिकर सहित कई अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारी भी इस चर्चा का हिस्सा बने। आज के वक्त में जब पूरी दुनिया आर्थिक उथल-पुथल और अनिश्चितताओं के दौर से गुजर रही है, तब भारत की आर्थिक नीतियों को बेहद सावधानी के साथ आगे बढ़ाने की जरूरत है। बैठक के दौरान इस बात पर विशेष रूप से मंथन किया गया कि कैसे देश के अंदरूनी विकास को गति दी जाए, रोजगार के नए अवसर पैदा किए जाएं और घरेलू उद्योगों को मजबूत किया जाए। सरकार की मंशा साफ है कि बिना किसी भटकाव के देश की नीतियों को सीधे तौर पर जमीनी फायदों से जोड़ा जाए।

हर हाल में देश बांग्लादेश लौटूंगी- शेख हसीना

ढाका (एजेंसी)। बांग्लादेश में 2024 में बड़े पैमाने पर हुए जनविद्रोह के बाद सत्ता से बेदखल की गईं पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि वह अगले महीने (भारत में) निर्वासन से स्वदेश वापसी के अपने इरादे पर कायम हैं। हसीना ने यह बात



ऐसे समय कही है, जब उनकी सरकार द्वारा प्रदर्शनकारियों पर की गयी घातक कारवाई के मामले में उन्हें मौत की सजा सुनाई जा चुकी है। छात्रों के नेतृत्व वाले विरोध-प्रदर्शनों के कारण सत्ता से हटाये जाने के बाद हसीना भारत आ गई थीं और तब से वह वहीं रह रही हैं। बांग्लादेश के एक विशेष न्यायाधिकरण ने 2025 में उन्हें मानवता के खिलाफ अपराध के लिए मौत की सजा सुनाई। अदालत ने माना कि वह उस कारवाई का आदेश देने के लिए जिम्मेदार थीं जिसमें सैकड़ों लोग मारे गये और हजारों अन्य घायल हो गये। संयुक्त राष्ट्र ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि इस दौरान लगभग 1,400 लोग मारे गये थे। हसीना ने किसी भी तरह की गलत कारवाई से इनकार किया है। उन्होंने न्यायाधिकरण के फैसले को भी खारिज कर दिया है और इस मुकदमे की वैधता को चुनौती दी है। बांग्लादेश ने कई बार हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की है, लेकिन भारत ने उन्हें सौंपने से इनकार कर दिया है। उन्होंने पहली बार अगस्त में दिसंबर में देश लौटने का इरादा जताया था।